International Journal of Education and Science Research Review
Volume-I, Issue-5 October- 2014 E-ISSN 2348-6457
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में कृषि एवं औद्योगिक विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मनोज कुमार
शोधकर्ता
सन राइज विश्वविद्यालय, अलवर

डा0वी0के0तोमर
शोध निर्देशक
सन राइज विश्वविद्यालय, अलवर

सार–
उत्तम पोषण उत्तम स्वास्थ्य का जनक है। पोषक तत्त्व ही शरीर की सामान्य वृद्धि एवं विकास के आधार हैं। पोषक तत्त्वों के आधार पर यह ही उत्तम, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विचार शील जीवन जिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की खोज के बाद विज्ञान ने पुनः विज्ञान ने पोषण विज्ञान का आविष्कार किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रोटीन पर खोज करने पर उपरोक्त तथ्य संज्ञान में आया। वैज्ञानिकों ने गत वर्षों में पोषक तत्त्वों एवं स्वास्थ्य को बहुत करीब से परखने की कोशिश की एवं इस ओर विशेष ध्यान दिया। यह उगती हुई स्वीकारोक्ति है कि जीवन के प्रथम चरण में उत्तम पोषण उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्तम जीवन का आधार है। परन्तु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक विकास में पोषण एवं कुपोषण का महत्त्व बाधक है। यह वास्तविकता है कि पोषक तत्त्व भूमि की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता से सम्बन्धित होते हैं। अधिक उत्पादक भूमि में पोषक तत्त्वों का स्तर ऊँचा एवं कम उत्पादक भूमि में पोषक तत्त्वों का स्तर नीचा होता है। परन्तु कहीं–कहीं अपवाद भी मिलता है तथा कम उत्पादक भूमि में भी पोषक तत्त्वों का स्तर ऊँचा पाया गया है। शायद ऐसा इस क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से भी सम्भव हो सकता है।

प्रस्तावना–
आज भारत राष्ट्र की जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ रही है उस अनुपात में न तो खाद्यानों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और न ही ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हो रही है। अतः राष्ट्र के सामने चिन्ता का विषय यह है कि यदि इसी गति से यह जनसंख्या बढती रही तो वह दिन दूर नहीं, जब भारत राष्ट्र विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा और हम इस कृषि प्रधान देश की जनसंख्या की पर्याप्त मात्रा में भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेंगे। अतः अब राष्ट्र के सम्मुख एक ही विकल्प है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में नई तकनीकों, बीजों, उर्वरकों का प्रयोग करके प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करें। बेकार पड़ी बंजर, ऊसर परती व अन्य कृषि योग्य भूमि को कृषि के अन्तर्गत उपयोग में लायें। ग्रामीण अविकसित क्षेत्रों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी को कम किया जा सके। आज लोग रोजगार भी तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर समाप्त होते नजर आ रहे हैं। शहरों में जनसंख्या का अतिक्रमण हो रहा है। पानी, बिजली और यातायात व प्रदूषण जैसी गम्भीर समस्याओं से शहरी जनसंख्या को सामना पड़ रहा है। यदि हम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण द्वारा जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर जुटाने होंगे तभी शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन रूक सकेगा।
यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों को विकास को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा समय–समय पर समितियॉ गठित की जा रही है। इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास अप्रैल 1960 में हुआ जब लघु उद्योग की पहल पर ग्रामीण औद्योगीकरण एवं लघु व मध्यम उद्योगों के द्वारा अविकसित क्षेत्रों के विकास की समभावनाऐं तलाशने के लिए ब्यउउपजजमम वद क्पेचमतेंस वि प्दकनेजतपमे गठित की गई। योजना आयोग द्वारा जनवरी 1964 में गठित पटेल समिति ने उत्तर प्रदेश के अविकसित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सुझाव दिये।
स्वतंत्रता के उपरान्त भारत सरकार ने कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए जिस योजना आयोग की स्थापना की थी उसका प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादों को विपणन में सुधार लाना एवं उद्योगों का विकास करना था। यद्यपि सरकारी प्रयासों से वर्तमान में, कृषि में उत्तम तकनीकों के प्रयोग से विकास हो रहा है। सरकार की औद्योगिक नीति का प्रयोग करके औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाने में कृषि अपना सक्रिय योगदान दे रही है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हमें अपने प्रयासों की सक्रियता में निरन्तरता बनाये रखनी होगी।

अध्ययन क्षेत्र–

कृषि एवं औद्योगिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश के नव सृजित कासगंज जनपद का चयन किया गया है। जनपद की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है। जनपद की लगभग 62 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। कृषि के अतिरिक्त कुछ लोग दुग्धपालन, मुर्गी पालन, आलू के चिप्स एवं पापड़ बनाने एवं कृषि सम्बन्धी अन्य उद्योगों में संलग्न हैं। शहरी क्षेत्रों की स्थापना के लिए भूमि एवं जल जैसे मूलभूत संसाधनों की प्रचुरता में आवश्यकता है। यहां पशुधन, खनिज एवं सामान्य श्रेणी के मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जनसंख्या की अधिकता के कारण यहां पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक एवं विविध उत्पाद सम्बन्धी साधन उपलब्ध है। साथ ही जनसंख्या की अधिकता के कारण खपत के लिए बाजार सम्बन्धी प्रबल सम्भानाऐं कृषि फसलों पर आधारित उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करती है।

कासगंज जनपद सघन कृषि फसलों का क्षेत्र है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से जनपद आज भी पिछड़ा हुआ है। जिसके कारण रोजगार की दर भी कम रही है। यहॉ पर औद्योगिक विकास सूती बस्त्र उद्योग, मूंगफली तेल उद्योग, मेंन्था उद्योग, आलू के चिप्स उद्योग, चीनी उद्योग आदि तक ही सीमित रहा है। यदि जनसंख्या एवं कृषि पर आधारित उद्योगों का अवलोकन किया जाये तो बहुत सारी असमानताऐं देखने को मिलती हे। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिए कृषि फसलों पर आधारित उद्योगों की स्थापना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध कार्य इसी दिशा में एक प्रयास है।

यह जनपद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह गंगा जमुना के दो आब के मध्य स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा पर गंगा नदी इस जनपद को बदायूँ जनपद से पृथक करती है। पश्चिम में अलीगढ, दक्षिण में एटा पूर्व में फर्रूखाबाद जनपद स्थिति हैं। इस जनपद की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 70किमी0 तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 49 किमी0 है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद में तीन तहसीलें 7 विकास खण्ड है। तहसील कासगंज में कासगंज, सहावर में सहावर, सोरों, अमॉपुर, पटियाली में पटियाली, गंजडुण्डवारा, सिढ़पुरा विकास खण्ड हैं। इस जनपद में 8 नगर 365 ग्राम हैं।

शोध का महत्व या शोध का उद्देश्य–

भारत वर्ष एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से ही अपनी जीविका चलाती है। अधिकांश मनुष्य जिनके नाम पर कृषि नहीं है, वे भी कृषक कर्मचारी के रूप में कृषि पर आधारित हैं। आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि उपलब्ध कराती है। राष्ट्र की आय का 50 प्रतिशत भाग भी इसी कृषि से प्राप्त होता है। देश के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरी ओर इसके माध्यम से पशुधनों को संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि हरे तथा सूखे चारे के रूप में उन्नत कृषि क्षेत्र की आपूर्ति सदैव महत्वपूर्ण रही है।

कृषि की दूसरी विशेषता यह भी है कि यह राष्ट्र के लगभग 70 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार प्रदान कराती है। इस प्रकार राष्ट्र के आन्तरिक एवं वाहय दोनों प्रकार के विकास में कृषि का योगदान रहा है। कासगंज जनपद में पिछड़ी जाति का बाहुल्य होने के कारण आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग कम मात्रा में किया जा रहा है। इसका प्रभाव कृषि उत्पादन एवं पूंजी निर्माण पर भी पड़ा है। अतः इस शोध कार्य के अन्तर्गत आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन एवं पूंजी निर्माण पर पड़ने वाले प्रभावों को भी स्पष्ट किया जायेगा तथा कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए पूर्व प्रयास किये जायेंगे।

उपकल्पना–

जनपद कासगंज में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों का अध्ययन मूलतः विवरणात्मक होगा, लेकिन निदानात्मक पक्ष पर भी प्रकाश डाला जायेगा। अध्ययन को उचित दिशा निर्देश देने हेतु निम्न उपकल्पनायें निर्मित की गयी हैं। जिनका परीक्षण करने का प्रयास शोधार्थी करेगा।

1. कासगंज जनपद का अधिकांश भाग आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है नगरीय क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र अधिक अविकसित है।
2. अविकसित क्षेत्रों के कृषक एवं कृषि श्रमिक निर्धन एवं शोषित है।
3. इनकी आर्थिक दशा सुधारने, सामूहिक क्रय शक्ति विकसित करने एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहकारी आन्दोलनों को प्रारम्भ किया गया है।
4. जनसंख्या की आय के श्रोत कम हैं परिणामतः ऋण को पूर्णतः अदा करने में असमर्थ है।
5. ग्रामीण क्षेत्र विकासित नहीं है।

6. ग्रामीण क्षेत्र जो यातायात की सुविधा से वंचित है, बहुत पिछड़े है।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों का विकास भी नहीं हुआ है। अतः इन उद्योगों के विकास हेतु पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

शोध अध्ययन विधि–

प्रस्तावित शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़े दैवनिर्दशन विधि द्वारा निम्नलिखित प्रकार एकत्रित किये जायेंगे।

1. प्रथम चरण – प्रत्येक तहसील से एक–एक विकास खण्ड का चयन।
2. द्वितीय चरण – प्रत्येक विकास खण्ड से 20 गांवों का चयन।
3. तृतीय चरण – प्रत्येक चयनित गांव से 10–10 परिवारों का चयन। कृषि परिवारों से सूचना अनुसूची बनाकर एकत्रित की जायेगी।

द्वितीय आंकड़े निम्नांकित श्रोतों से प्राप्त किये जायेगे

1. विकास खण्ड स्तर कार्यालय से।
2. तहसील स्तर कार्यालय से।
3. जिला कृषि अधिकारी।
4. जिला सांख्यिकीय अधिकारी।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या उ0प्र0।
6. उ0प्र0 कृषि उत्पादक आयुक्त।
7. नियोजन जन विभाग उत्तर प्रदेश।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. Bhatia, S.S. 1967 Measure of Agricultural efficiency in U.P. Ecomopri cyeogapics Volume 03
2. Singh J and Dhillom SS 1982 Agricultural Geography
3. Momoria, C.B. 1986 Agree problems of Jhoj Kitab Mahal Pvt. Allahabad
4. Amani, K2 1986 Agricultural leneluse in Aligarh distance
5. Barsal, P.C. 1988 Agricultural problems in India
6. Givis V.V. 1988 Lavome problems in India Industries
7. Chopara K 1998 Agricultural development in Punjab
8. सिग वी.पी. 1998 कृषि भूगोल
9. Dr. Panday, J.N. 1999 कृषि भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर Geography Vol. 02
10. Sharma B.L. 1999 कृषि भूगोल
11. Tiwari, R.C. 1999 कृषि भूगोल
12. Agrawal N.N. 1999 Development of Large Scale, India sties in U.P.
13. नायणी पी.एन. 2000 सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण